प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 45 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 13 – 20 नवम्बर 2017 मूल्य पांच रूपए

कांग्रेस और भाजपा दोनो ही कर रहे सरकार बनाने के दावे

शिमला/शैल। चुनाव के नतीजे 18 दिसम्बर को आने है और 18 दिसम्बर तक का यह समय चुनाव लडने वाले हर उम्मीदवार के लिये एक कड़ी परीक्षा का समय है क्योंकि इस दौरान उसे अपने समर्थकों और मतदाताओं के बीच रहना और इस नाते उसे हर समय यह दावा बनाये रखना है कि वह जीत रहा है। राजनीतिक दलों को तो यह दावा सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच रखना है। इसी राजनीतिक अनिवार्यता के चलते सत्तारूढ़ कांग्रेस और सत्ता पर कब्जे के लिये तैयार बैठी भाजपा ने सरकार बनाने के दावों की रस्म अदायगी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। मतदान के बाद भाजपा अपनी आकलन बैठक कर चुकी है और कांग्रेस की यह बैठक 28 को होने जा रही है।

चुनाव टिकटों के आवंटन के बाद दोनों दलों में बगावत देखने को मिली है। टिकट के कई प्रबल दावेदारों ने टिकट न मिलने पर बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा है ऐसे विद्रोहीयों की संख्या दोनो दलों में लगभग बराबर रही है। ऐसे विद्रोहीयों और उनके समर्थकों को दोनों दल निष्कासित भी कर चुके हैं। लेकिन निष्कासन के बाद भी दोनो दलों को भीतरघात का सामना भी करना पड़ा है। भीतरघात एक ऐसा कृत्य है जिसे प्रमाणित कर पाना बहुत आसान नही होता है। भाजपा की हमीरपुर में हुई बैठक में करीब हर ब्लॉक से भी भीतरघात की शिकायतें आने की चर्चा है। इन शिकायतों पर विचार-विर्मश के बाद इन्हे सांसद वीरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति को अगली कारवाई के लिये भेजने का फैसला लिया गया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इस बैठक में पार्टी ने जो आन्तरिक सर्वे करवाया है उसके मुताबिक पार्टी को 38 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में बिलासपुर की चार में से तीन सीटें जीतने का दावा किया गया है। इसमें पार्टी झण्डूता में जीत को लेकर आश्वस्त नही है। झण्डूता में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है क्योंकि यहां केवल दो ही उम्मीदवार मैदान में थे। इस नाते यहां पर पार्टी की विचारधारा और चुनावी रणनीति दोनो की स्वीकारयता की कसौटी परख दाव पर है। फिर यहां एक दशक से भाजपा का कब्जा भी चला आ रहा है। उम्मीदवार भी पहले उम्मीदवार से किसी कदर कम नही था। ऐसे में यदि पार्टी अपने ही आन्तरिक आंकलन में इस सीट को लेकर आश्वस्त नही है तो पार्टी के सारे आंकलनों पर स्वयं ही एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

फिर हर ब्लॉक से भीतरघात की शिकायतों का आना भी इसी ओर संकेत करता है कि पार्टी को अपने ही लोगों ने बडे पैमाने पर नुकसान पंहुचाया है। सूत्रों की माने तो कुछ बडे नेताओं ने दूसरे बडे नेताओं को हटवाने के लिये एक दूसरे के विरोधीयों की धन से भी मदद की है। माना जा रहा है कि इस तरह के भीतरघात से पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा है क्योंकि जब बडे नेता ही इस तरह की गतिविधियों को अपना अपरोक्ष समर्थन देंगे तो उससे नुकसान तो अवश्य पंहुचेगा। चर्चा है कि जब तक पार्टी ने धूमल को नेता घोषित नही किया था तब तक इस तरह के भीतरघात की संभावनाएं बहुत कम थी क्योंकि तब तक सामूहिक नेतृत्व के तहत ही यह चुनाव लडे जाने की बात चल रही थी। लेकिन जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा का जंजैहली में जय राम ठाकुर को लेकर यह ब्यान आ गया कि चुनाव के बाद उन्हे एक बडी जिम्मेदारी दी जायेगी, इस ब्यान के साथ ही नड्डा का एक साक्षात्कार छप गया जिसमें यह कहा गया कि ऐसा मुख्यमन्त्री दिया जायेगा जो आगे पन्द्रह वर्षो तक नेतृत्व दे पायेगा। इस साक्षात्कार के सामने आने के बाद स्वभाविक रूप से पार्टी के भीतरी समीकरणों में बदलाव सामने आने लगे। इसी के साथ चुनाव अभियान की जो भ्रष्टाचार केन्द्रित रणनीति अपनाई गयी थी उस पर हर पत्रकार वार्ता में नेताओं को कडे सवालों का सामना करना पड़ा। पंडित सुखराम और उनके परिवार को भाजपा में शामिल करके कांग्रेस के टूटने की जो उम्मीद की थी वह भी सफल नही हो पायी। उल्टे सुखराम का अपना भ्रष्टाचार भाजपा के गले की फांस बन गया। हर रोज भाजपा को इस पर सफाई देने की नौबत आ गयी। इस परिदृश्य में जब पूरे हालात की पुन: समीक्षा की गयी तब धूमल को नेता घोषित करने के अतिरिक्त पार्टी के पास कोई विकल्प नही रह गया था। लेकिन कुछ लोगों को धूमल का नेता घोषित होना पसन्द नही आया है। बल्कि कई जगह तो भीतरघात के तार सीधे इन लोगों से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद इस संद्धर्भ में भाजपा के अन्दर काफी कुछ रोचक देखने को मिलेगा यह तय है।

इसी तर्ज पर कांग्रेस के अन्दर भी बडे पैमाने पर भीतरघात होने की चर्चा बाहर आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस के अधिकांश विद्रोही तो सीधे-सीधे वीरभद्र सिंह के साथ जुड़े हुए माने जा रहे हैं। पार्टी ने चुनाव आंकलन के लिये 28 को बैठक बुलाई है। इस बैठक में भीतरघात की कितनी शिकायतें प्रदेश भर से आती है और उन पर क्या कारवाई की जाती है इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही सामने आयेगा। लेकिन इस दौरान पार्टी के कुछ हल्कों में वीरभद्र के ईडी मामले को लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। क्योंकि 2012 में वीरभद्र ने चुनाव में जो शपथ पत्र सौपा था उसे सीबीआई ने अपनी जांच में झूठा पाया है। सीबीआई इस तथ्य को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने रख चुकी है। उच्च न्यायालय ने इस शपथपत्र को चुनाव आयोग को अगली कारवाई के लिये भेजने की सिफारिश 31.3.17 को की थी। वीरभद्र ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय खरिज कर चुका है। अब वीरभद्र के विरोधी इस कानूनी कमजोरी का चुनाव परिणामों के बाद लाभ उठाने की रणनीति बना रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव परिणामों के बाद वीरभद्र के लिये स्थितियां सुखद रहने वाली नहीं है।

एनजीटी के आदेशों से सरकार की रिटैन्शन पॉलिसी सवालों में

आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बन रही रणनीति

शिमला/शैल। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के सारे **"Green forest and core areas"** में हर तरह के निमार्ण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यही नही राष्ट्रीय उच्च मार्गो के तीन मीटर के दायरे में भी यह रोक लगा दी है। प्रदेश में हुए अन्धा धुन्ध निमार्ण पर सरकार की प्रताड़ना करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा है कि **"If such unplanned and indiscriminate development is permitted, there will be irreparatable loss and damage to the environment, ecology and natural resources on the one hand and inevitable disaster on the other"** ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के पहाड़ को काटने या वन क्षेत्र को नुकसान का दोषी पाया जाता है तो हर दोष के लिये उस पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जायेगा। नये निर्माणों पर ट्रिब्यूनल ने कहा है कि **"Beyond the core, green /forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the Town and Country Planning Act. Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor."**

However, if any construction particularly public utilities (buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeyes plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the authorities concerned having jurisdiction over the area in question."

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये निदेशक टीसीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में सचिव शहरी विकास विभाग, निदेशक वाड़िया इन्स्टीच्यूट ऑफ हिमालय जियालोजी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के अधिकारी और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव शामिल हैं। यह कमेटी सरकार को **This committee shall also advise the state of Himachal Pradesh for regulating traffic on all roads, declaring prohibited zones for vehicular traffic, preventing and controlling pollution and for management of municipal solid waste in Shimla. The recommendation of**

शेष पृष्ठ 8 पर.....

ऊर्जा संरक्षण में हर व्यक्ति निभाए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे ऊर्जा बचत की दिशा में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और आवश्यकतानुसार ही बिजली का उपयोग कर राष्ट्रीय संपत्ति की बचत करें। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचत की दिशा में प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जाएगा।

आचार्य देवव्रत ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों से भी अपील की कि वे संबंधित जिले में सभी कार्यालयों को इस बाबत निर्देश जारी करें। इससे बिजली की बचत तो होगी ही साथ ही इस धनराशि का उपयोग प्रदेश के विकास व गरीब लोगों की मदद में उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण की दिशा में दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाये जा सकते। जिस एहतियात से घर पर हम बिजली का उपयोग करते हैं उसी तरह सरकारी कार्यालयों में भी ऊर्जा बचत को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए, जो प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लेकिन उन्हें व्यवहार में भी लाया जाना चाहिए, जिसके लिए लोगों को जागृत किए जाने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद गत वर्षो के दौरान राजभवन ने ऊर्जा बचत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। गत दो वर्षो में राजभवन ने 12 लाख रुपये से अधिक की बिजली बचत की है और इस वर्ष ही 8 लाख की बिजली बचत हुई है, जो एक बेहतर कार्यसंस्कृति को विकसित करने की दिशा में प्रयास है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं हरियाणा राज्य, जो गर्म क्षेत्र है, से संबंधित हैं। बावजूद इसके, उन्होंने दो वर्षो से राजभवन में सेंट्रल हीटिंग का उपयोग नहीं किया है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तौर पर राजभवन कार्यालय में बिजली नहीं जलाई जाती है, जो बचत का प्रमुख कारण है। इसके लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आशा जताई कि ऐसा ही प्रयास प्रदेश के अन्य बड़े कार्यालयों में भी होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन की अपार क्षमताएं मौजूद हैं और राज्य द्वारा इसका निष्पादन भी किया जा रहा है। बावजूद इसके, प्रदेश अन्य राज्यों से भी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ समयावधि में बिजली लेकर कमी को पूरा करता है। इससे राज्य के वित्तीय कोष पर बोझ पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में यदि हम सामुहिक प्रयास करें तो इस खर्चे से बचा जा सकता है।

राज्यपाल राजभवन में ऊर्जा संरक्षण पर आयोजित बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र को भी घर का हिस्सा समझना चाहिए। ऐसी सोच व चिंतन को विकसित किया जाना चाहिए कि सरकारी कार्यालय आजीविका का माध्यम ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अवसर भी प्रदान करता है।

हज यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के इच्छुक व्यक्ति हज यात्रा 1439 (एच) – 2018 के लिए आवेदन पत्र 7 दिसम्बर, 2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भारतीय हज समिति की वैबसाईट www.hajcommittee.comपर उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के साथ मूल पासपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है, जिसकी वैधता कम से कम 14 फरवरी, 2019 तक होनी चाहिए। आवदेन पत्र में प्रतिव्यक्ति 300 रुपये की दर से प्रक्रिया फीस की बैंक रसीद (अप्रत्यर्पणीय), जो भारतीय हज कमेटी के एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 35398104789 अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकांउट नंबर 318702010406010 (शाखा नाम, कोड और ट्रांजेक्शन आईडी – बैंक जरनल नंबर), बैंक का खाली चेक, जिसे कैंसल किया हो अथवा बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी अथवा बैंक का नाम, शाखा कोड, शाखा नाम व आईएफएस कोड को दर्शाता बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, 14 नवम्बर, 2017 को 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति जो आरक्षित श्रेणी – ए में आते हैं, द्वारा सादे कागज पर इसकी घोषणा शपथ, आवेदनकर्ता के 3.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर आकार के नवीन रंगीन फोटोग्राफ, जो श्वेत बैकग्राउंड पर खींचे हों संलग्न करने होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि चिकित्सा जांच तथा फिटनेश प्रमाण पत्र सहित अन्य विवरण आवेदन पत्र पर उपलब्ध हैं, जिन्हें भारतीय हज समिति की वैबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र हि.प्र. राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी को हि.प्र. सचिवालय योजना भवन कमरा संख्या 104 स्थित उनके कार्यालय में निर्धारित तिथि तक पहुंच जाने चाहिए। 7 दिसम्बर, 2017 के पश्चात् प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल ने चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में सतलुज जल विद्युत निगम लिमीटेड द्वारा 'ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान' को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया।

यह प्रतियोगिता भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान के तहत आयोजित की गई।

आचार्य देवव्रत ने बच्चों से अपने परिवारों, पड़ोसियां और समाज को ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे में प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वे ऊर्जा संरक्षण के लिए आगे आए।

उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में सृजनात्मक क्षमता होती है, जिसकी अभिभावकों व अध्यापकों द्वारा सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम आते हैं। उन्होंने लोगों का ऊर्जा संरक्षण के प्रति सोच में बदलाव लाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्त्रोत की संख्या सीमित है और इन स्त्रोतों के अन्धाधुंध दोहन से बचना होगा तथा इनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बच्चों को अनुशासन, देशभक्ति के मूल्य पढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सकें। उन्होंने अध्यापकों से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण व समाज की सेवा के प्रति जागरूक करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने एसजेवीएनएल का विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां विशेषकर ऊर्जा संरक्षण में दिए गए योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से और अधिक कठिन परिश्रम करने को कहा ताकि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सही प्रकार से सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि समर्पण व कठिन परिश्रम से ही जीवन में निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण पर एसजेवीएनएल की प्रेरणा से राजभवन में ऊर्जा के दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और इन पगों से एक वर्ष के दौरान आठ लाख रुपये से अधिक की बचत हुई है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रतियोगिता में आए प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमश: 20 हजार रुपये, 15 हजार रुपये व 10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार के अतिरिक्त 2500 रुपये प्रति श्रेणी के 10 सांतवना पुरस्कार भी वितरित किए।

एसजेवीएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्याम सिंह नेगी ने राज्यपाल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में प्रथम स्तर पर प्रदेशभर के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 4,52,371 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष दो श्रेणियों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्रेणी ए में चौथी कक्षा से छठी कक्षा तक तथा श्रेणी बी में सातवीं से नवीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ए श्रेणी के विजेता दिसम्बर, 2017 में नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त महा प्रबन्धक विजय प्रसाद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महा प्रबन्धक ए.के. मुखर्जी प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक एम.एल.आजाद, निर्णायक मण्डल विद्यार्थी व एसजेवीएनएल के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नौणी विवि में 25वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन

शिमला/शैल। राज्य स्तर की बाल विज्ञान कांग्रेस का रजत जयंती संस्करण का नौणी स्थित डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में समापन हुआ। इस अवसर पर एपीजी विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ तेज प्रताप मुख्य अतिथि रहे।

नौणी विवि के उप – कुलपति डॉ एचसी शर्मा, सीएसआईआर के निर्देशक (एनसीएसटीसीई)डॉमनोज परटेरिया, डॉ बीके त्यागी और शूलिनी विवि के उप – कुलपति डॉ पी. के खोसला ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। सोलन उपायुक्त राकेश कंवर और एसपी मोहित चावला ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश में स्कूली छात्रों का यह सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम हैं, जिसमें विभिन्न जिलों से प्रतियोगिता जीतकर छात्र इस काँग्रेस के लिए चुने गए हैं। इस बार इस प्रोग्राम में 11 जिलों से लगभग 1000 छात्र और शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस साल इस कांग्रेस का विषय 'सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार' था।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने सभी छात्रों को उनके नायाब विचारों को साइन्स के माध्यम से म डल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सहरना की। नौणी विवि के उप कुलपति डॉ एचसी शर्मा ने प्रतिभागियों को जीवन की आम समस्याओं का समाधान प्रकृति में खोजने का सुझाव दिया। उन्होनें कहा कि हमें उन तकनीकों और आविष्कारों पर काम करने जरूरत है, जिसका फायदा सभी वर्गो के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। इस मौके पर डॉ खोसला ने सभी छात्रों को विज्ञान को एक कैरियर के रूप में अपनाने पर जोर दिया। छात्रों को अपने व्याख्यान सोलन उपायुक्त राकेश कंवर ने विफलता को सही तरीके से संभालना और किसी भी कॉम्पटिशन, विशेष रूप से परीक्षा का, कोई भी दबाव अपने ऊपर न लेने का सुझाव दिए।

हिमास्कोस्ट के संयुक्त सदस्य सचिव कुणाल सत्यार्थी ने अपने संभोधन में सभी विद्यार्थियों को अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का बारे में जानने का सुझाव दिया। उन्होनें कहा कि हमें अपने संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। हर चीज को दूसरे ढंग से करने और प्रश्न करने की आदत डालने की बात उन्होनें कही।

हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (HIMCOSTE) ने यह आयोजन नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन और हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर किया।

चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, छात्रों ने विज्ञान के म डल, प्रश्नोत्तरी, गणित ओलंपियाड, वैज्ञानिक रिपोर्टिंग, गतिविधि कोर्नर और वैज्ञानिक विषयों पर आधारित स्किट (skit) में भाग लेंगे। वैज्ञानिक रिपोर्टिंग, म डल और स्किट में प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की गतिविधि में भाग लेंगे का मौका मिलेगा।

विज्ञान स्किट प्ले कॉम्पटिशन में जहां जिला कुल्लू प्रथम स्थान हासिल किया वहीं सोलन और चंबा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। क्विज कॉम्पटिशन में हमीरपुर जिले के छात्रों को सयुंक्त रूप से चैम्पियन घोषित किया गया। साइन्स म डल में चंबा जिले के जीएसएसएस चोवारी के छात्र अंकित का बेहतर जीवन शैली म डल ने बाजी मारी। गीता आदर्श विद्यालय सोलन से शूलिनी का बहु उपयोगिता वाहन दूसरे और मिनेरवा पब्लिक स्कूल की छात्र मान्या नड्ड़ा का रेल्वे सेफ्टी सिस्टम तीसरे स्थान पर रहा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
संयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

'मीडिया के समक्ष चुनौतियां' विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर संगोष्ठि

शिमला/शैल। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय 'मीडिया के समक्ष चुनौतियां' रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख एवं वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. लोहमी ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र का सशक्त होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है, परन्तु इसकी पूर्ण स्वतंत्रता तभी कायम रह सकती है, जब लोकतंत्र के अन्य तीन स्तम्भ सशक्त होंगे।

उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता हर क्षेत्र की जरूरत है लेकिन मीडिया तथा न्यायपालिका में विश्वसनीयता अतिआवश्यक है और इसके अभाव में समाज में अराजकता उत्पन्न होना स्वभाविक है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता का कम होना, अखबार बन्द होने से अधिक खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि मीडिया सामाजिक सरोकारों को सही परिपेक्ष्य में उजागर करें, ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह भी आवश्यक है कि लोगों में मीडिया के प्रति विश्वसनीयता के लिए रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हों।

लोहमी ने कहा कि स्वतंत्र, निर्भीक एवं तटस्थ मीडिया के लिए यह भी आवश्यक है कि वह बिना किसी के प्रभाव में आए रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में मीडिया को उचित सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह बदलते परिप्रेक्ष्य में निरन्तर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक तथा न्यू मीडिया एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए तभी एक सशक्त समाज में वे अपनी बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यू मीडिया को भी अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा, तभी उसकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है।

लोहमी ने कहा कि एक समय था, जब समाचार पत्रों में स्थान का अभाव होता था, परन्तु आज एक समचार पत्र की अनेक संस्करण के कारण हर समाचार को स्थान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 'पेड न्यूज' मीडिया के लिए सही मायनों में चुनौती है और यह आवश्यक है कि इससे प्रभावित होकर मीडिया अपनी विश्वसनीयता न खोएं। उन्होंने कहा कि सही शब्दों में सूचना जन सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया नागरिकों

के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि अनेक चुनौतियों के बावजूद भी प्रिंट मीडिया की महतता कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई तथा आधुनिक भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेशक सोशल मीडिया आज मीडिया के नये चेहरे के रूप में उभर कर समाने आया है, लेकिन प्रिंट मीडिया की आज भी उतनी ही लोकप्रियता एवं विश्वसनीयता है।

मल्होत्रा ने कहा कि हमारे देश में प्रिंट मीडिया 8 प्रतिशत की दर से विकसित हो रहा है जबकि विदेशों में स्थिति विपरीत है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में चुनौतियां पीढ़ी दर पीढ़ी रही हैं, लेकिन सामर्थ्य और इच्छाशक्ति से इनका समाधान कोई अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का न केवल पथ प्रदर्शक है बल्कि सजग प्रहरी है। उन्होंने कहा कि भविष्य हमेशा ही सुनहरा होता है और बदलाव समाज की आवश्यकता तथा प्रकृति का नियम है। उन्होंने कहा कि मनुष्य और समाज के सशक्तिकरण के लिये जानकारी होना अनिवार्य है और ज्ञान के लिये मजबूत पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए।

न्यूज-18 के सम्पादक डा. शशि भूषण ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया के कारण मीडिया के क्षेत्र में बृहद बदलाव आया है, लेकिन इसके बावजूद पत्र-पत्रिकाओं का आज भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन अब इसके स्वरूप में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ है, लेकिन आग चलकर यह प्रतिस्पर्धा प्रिंट मीडिया के साथ भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जानकारी को तोड-मरोड़ कर अपनी सुविधा के अनुरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इसकी प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। सोशल मीडिया पर परोसी जा रही जानकारी कितनी सही है, इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है जो इसे संशय के घेरे में खड़ा करती है।

दैनिक जागरण की संपादक डॉ. रचना गुप्ता ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर में समाचार पत्रों का महत्व और अधिक बढ़ा है परन्तु साथ ही साथ इसके लिए चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पाठकों को बांधे रखना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह आवश्यक है कि समाचार पत्रों में रूचिकर व सम-सामायिक पाठ्य सामग्री हों तथा इसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को हर वर्ग के पाठकों की रूचि का ध्यान रखना होगा, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि बेहतर रिपोर्टिंग के लिए शोध व संदर्भ का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग को बेहतर व सूचनाप्रद बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि उसमें अधिक से अधिक सूचना का समावेश हो।

हि.प्र. विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डा. शशिकांत शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सोशल मीडिया का तेजी से प्रसार हो रहा है और आज यह मीडिया प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने एक बड़ी चुनौति के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा हालांकि सोशल मीडिया की अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है और न ही इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण व अंकुश है, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा बेशक हमारे देश में समाचार पत्रों की वृद्धि दर मे बढ़ौतरी हुई है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहलाए जाने वाले प्रेस को अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिये संघर्षशील रहना होगा।

डा. शशिकांत शर्मा ने कहा कि आज समाचारों की परिभाषा बदल रही है। उन्होंने कहा कि यदि आज प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना स्वरूप नहीं बदला तो सोशल मीडिया इसका स्थान ले लेगा। मीडिया मोबाईल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल साईटस मीडिया व समाज दोनों के लिये बहुत बड़ी चुनौति है और ऐसे में हमें स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता की सोच को कायम रखना है तथा पत्रकारिता के नियम व सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना है। परिचर्चा में मीडिया कर्मियों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।

सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों में हिमाचल गौरव पुरस्कार, प्रेरणा स्त्रोत सम्मान तथा सिविल सेवा पुरस्कार शामिल हैं, जो हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2018 को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग में नामांकन अथवा संस्तुतियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2017 है।

संस्तुतियां निर्धारित प्रपत्र पर हिन्दी में अधिक से अधिक दो पृष्ठों में उपलब्धियों के एक संक्षिप्त विवरण सहित प्रस्तुत करने को कहा गया है। नामांकन में सत्यापित की गई उत्कृष्ट एवं असाधारण उपलब्धियां अथवा सेवाएं, जो पात्र व्यक्ति अथवा संस्था की संस्तुति को न्यायसंगत सिद्ध करती हो, का उल्लेख होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि संस्तुतियां प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रपत्र पर केवल वांछित व सम्बद्ध दस्तावेज ही सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। नामांकन भेजने के लिए योजनाओं सहित निर्धारित प्रपत्र सरकार की वैबसाईट ww.himachal.nic.in हंक पर उपलब्ध हैं।

जम्मू-कश्मीर में फूलों की खेती को लोकप्रिय बनाने में नौणी विवि के वैज्ञानिक कर रहे मदद

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (यूएचएफ), नौणी का योगदान न केवल अपने राज्य में रहा है बल्कि अन्य राज्यों में कई खेती सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विश्वविद्यालय परिसर में जम्मू और कश्मीर के सात सदस्यीय समूह का व्यवसायिक फूलों की खेती पर आधारित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी सात प्रतिभागी वर्तमान में जम्मू कश्मीर सरकार के औद्यानिकी विभाग में असिस्टेंट "लॉरिकल्चर ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। इस समूह के अधिकांश लोग अपने राज्य के प्रतिष्ठित गार्डन जिनमें टयूलिप गार्डन और मुगल गार्डन शामिल हैं, में काम करते हैं।

नौणी विवि के विस्तार शिक्षा निदेशालय ने पहले भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर औद्यानिकी विभाग का ही एक आठ सदस्यीय समूह, जिसमें दो अधिकारी और छह माली थे, को फूलों की खेती में प्रशिक्षण दिया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक और संयुक्त निदेशक (ट्रेनिंग) डॉ राजेश भल्ला ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यवसायिक फूलों की खेती में नवीनतम तकनीकों के बारे में अधिकारियों को अवगत करना है ताकि यहाँ सीखी गई चीजों को वह उन लोगों तक पहुंचायें, जो इससे अपना जीवन चलाते हैं।

कार्यक्रम में दौरान लिलियम, डैफोडील्स, जरबरा और कार्नेशन फूलों की खेती पर प्रशिक्षण दिया गया। इन फूलों की व्यवसायिक खेती दोनों ही राज्यों में की जा रही है। इसके अलावा व्यवहारिक सत्र और व्याख्यान के माध्यम से प्रतिभागियों को मिट्टी का विश्लेषण, जल गुणवत्ता, फसल उत्पादन तकनीक, उर्वरक, कीट और रोगों के बारे में सिखाया गया था। प्रशिक्षण के बारे में बारामुला में कार्यरत शकील अहमद ने बताया कि इस प्रशिक्षण से वो इस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम तकनीक के बारे में सीखकर, जम्मू और कश्मीर में फूलों की खेती को बढ़ाने के लिए काम करेगें।

हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, अधोसंरचना तथा समावेशी विकास में प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को इण्डिया टूडे ग्रुप द्वारा शिक्षा, अधोसंरचना और समावेशी विकास क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नई दिल्ली में इंडिया टूडे ग्रुप द्वारा आयोजित इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कनक्लेव-2017 के अवसर पर केन्द्रीय भूतल परिवहन, जहाज रानी एवं जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा नवीकरण मंत्री नितिन गडकरी से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'द पॉलीटिक्स ऑफ डेवेल्पमेंट: माई टर्न एराउण्ड स्टोरी' विषय पर सम्बोधन किया। उन्होंने प्रदेश के गठन से लेकर अब तक की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास का आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने डा. वाई.एस. परमार द्वारा हिमाचल प्रदेश की विकास की सुदृढ़ नींव रखने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने गठन के बाद अपनी विकास यात्रा आरम्भ की और आज यह विकास का आदर्श बनकर उभरा है। यह राज्य विकास मानकों में देश के बड़े राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और राज्य ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्य का सदृढ़ होना आवश्यक है यदि हम देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमें राज्यों को मजबूती प्रदान करनी होगी। उन्होंने प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुदृढ़ व विकसित राज्य केन्द्र सरकार को योगदान दे सकते हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 25 दिसम्बर, 2012 को राज्य की बागडोर संभाली है, तब से राज्य के संतुलित एवं समावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है, गरीब, दलित व कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अधोसंरचना के संतुलित विकास सहित गरीबों तथा वंचितों के उत्थान में ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। राज्य में पर्याप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थानों के अतिरिक्त सड़क सम्पर्क, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी निरन्तर वृद्धि हुई है।

उन्होंने इण्डिया टूडे ग्रुप द्वारा राज्यों द्वारा किए गए अच्छे कार्यो की सराहना के लिए ग्रुप के प्रयासों की प्रशंसा की। ग्रुप के सम्पादकीय निदेशक राजचंगप्पा ने मुख्य अतिथि तथा अन्यों का स्वागत किया।

बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

राष्ट्रीय प्रैस दिवस–कुछ सवाल

16 नवबर को राष्ट्रीय प्रैस दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन भारतीय प्रैस परिषद मीडिया से जुड़े किसी मुद्दे को मीडिया के सामने एक खुले चिन्तन और खुली चिन्ता के लिय संप्रेषित करती है। क्योंकि यह दिन और इस दिन चिन्तन के लिये आया विषय मीडिया के लिये अपने भीतर झांकने का विषय होता है। उम्मीद की जाती है कि इस अवसर पर मीडिया से जुड़ा हर कर्मी आत्मचिन्तन करके अपने लिये कुछ मानक तय करेगा। इस दिन निष्पक्षता से हर छोटा–बड़ा व्यक्ति जो अपने को मीडिया कर्मी मानता है इक्कठे बैठकर सामूहिक रूप से खुले मन से चिन्तन–मन्थन करेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है क्या हमारे प्रैस क्लब इस विषय में पूरी ईनामदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? या फिर यह दिन भी एक सरकारी आयोजन बनकर ही रह गया है। इस अवसर पर इस बार प्रैस परिषद द्वारा सुझाया गया विषय था ''मीडिया के सामने चुनौतीयां''। इस दिन षिमला में भी इस संद्धर्भ में प्रदेश के जनलोक संपर्क विभाग द्वारा एक आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिमला के तीन पत्रकारों ने इस दिन के विषय पर अपने–अपने विचार रखे। विचार रखने के बाद इस पर खुली चर्चा भी हुई। इसके लिये संद्धर्भित विषय किस वक्ता ने क्या कहा उसकी तफसील में जाने की बजाये मैं इस बिन्दु पर आऊंगा कि पूरे चिन्तन के बाद अन्त में सामने क्या आया और वह कितना महत्वपूर्ण और गंभीर था। सभी एक मत थे कि मीडिया इस समय विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहा है और सोशल मीडिया ही उसके लिये सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यह सही है कि यह मीडिया के लिये इस समय का सबसे बड़ा संकट है लेकिन इस संकट से बाहर कैसे निकला जाये इसका कोई रास्ता इस चिन्तन में निकल नही पाया। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि ''रास्ते '' का कोई प्रयास ही नही हुआ।

इस चिन्तन में रास्ता खोजने का प्रयास क्यों नही हो पाया इस पर बात करने से पहले यह कहना ज्यादा प्रसांगिक होगा कि इस अवसर पर शिमला में ही बैठे सारे मीडिया कर्मी उपस्थित नही रहे। शिमला में प्रदेश विश्वविद्यालय के अतिरिक्त इग्नू एपीजी गोयल विश्वविद्यालय में भी पत्रकारिता का विषय पढाया जा रहा है। यह अच्छा होता कि इन संस्थानों का भी पत्रकारिता विभागों के छात्र इस आयोजन में भाग लें क्योंकि भविष्य में उन्हें इन सवालों का सामना करना है। इसके लिये प्रदेश के लोक संपर्क विभाग के साथ मैं प्रैस क्लब के संचालकों से भी यह अपेक्षा करूंगा कि अगले वर्ष यह दोनों मिलकर इस दिन का आयोजन करें और सभी मीडिया कर्मीयों से भी उम्मीद करूंगा कि वह अपने–अपने अहम को छोड़कर इस आयोजन का हिस्सा बने और यह आयोजन पूरे दिन भर का कार्यक्रम रहे। भविष्य की इस कामना के साथ ही मैं इस विषय पर स्वयं क्या सोचता हूं उसे भी अपने सह धर्मीयों और पाठकों के साथ सांझा करना चाहूंगा।

मीडिया पहले विश्वयुद्ध के बाद से पत्रकारिता का पर्याय बन गया है। संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। मीडिया/संप्रेषण सूचना और संप्रेषण विचार का समाज और उसकी व्यवस्था में सूचना और विचार दोनों का अपना–अपना अलग महत्व है और दोनों की ही अपनी –अपनी भूमिका है। संभवत: इसी महत्व और भूमिका के कारण ही मीडिया को लोकन्त्र का चौथा खम्बा माना जाता है। समाज में चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या तानाशाही लेकिन दोनों ही व्यवस्थाओं कार्यपालिका और न्यायापालिका आवश्यक अंग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका तीसरे सतम्भ के रूप में जुडती है। हमारे यहां लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत यह यह तीनों अंग मौजूद हैं और तीनों का अपना–अपना दायित्व है इन तीनों पर नजर रखने के लिये जनता है। इसे जनता के अधिकार हासिल है कि वह पांच साल बाद व्यवस्था को बदल सकती है। जनता बदलाव तब करती है जब उसे लगता है कि उसके द्वारा चुनी हुई व्यवस्थापिका के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नही कर रही है। जब ऐसी स्थिति उभरती है तब मीडिया की भूमिका आती है। तब मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका पर एक ऐसे निगरान की भूमिका निभाये जो अपने में पूरी तरह निष्पक्ष भी हो। लेकिन जब व्यवस्थापिका सत्ता के लोभ में कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रभावित करना शुरू कर देती है तब सामाजिक व्यवस्था का सारा सन्तुलन बिगड़ जाता है। जब यह स्थिति पनपती है तब जनता भ्रमित होना शुरू हो जाती है। जिस जनता को इसी पूरी व्यवस्था का मालिक कहा जाता है जिसके सामने सारे तन्त्र की जवाबदेही मानी जाती है। वही जनता इसी व्यवस्था के सामने जब लाचारगी में आ जाती है तब जनता का इस स्थिति से बाहर निकालने की जिम्मेदारी केवल मीडिया के कंधों पर आ जाती है।

यह वह स्थिति होती जब जनता उसे मीडिया द्वारा प्रेषित सारी सूचनाओं और विचारों पर या तो तात्कालिक रूप से एकदम विश्वास कर लेती है और तब उस पर सकारात्मक फैसला लेती है या उस पर विश्वास न करके नकारात्मक फैसला लेती है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है और यहीं पर सत्ता पर काबिज या सत्ता पर कब्जा करने की चाहत वाला चाहे वह एक राजनीतिक दल हो या महज़ एक व्यक्ति वह मीडिया का सहारा लेता है। और यहीं से शुरू होता है मीडिया की विश्वसनीयता का प्रश्न। यदि मीडिया कर्मी ऐसी स्थिति का निष्पक्ष वौद्धिक आंकलन करके अपना पक्ष चुनता है तो उसकी विश्वसनीयता पर किसी भी तरह का संकट नही आता है। तब उस पर फेक न्यूज़ या पेड न्यूज़ के आक्षेप नही लगते हैं। लेकिन इसके लिये आवश्यक शर्त यह रहती है कि संबधित विषय पर उसका अध्ययन और जानकारी एकदम ठोस हो। जब ठोस अध्ययन और जानकारी के आधार पर व्यवस्था पर चोट करता है तब उसकी विश्वसनीयता अपने आप स्थापित हो जाती है। अध्ययन और जानकारी का अभाव ही उसे सवालों के घेरे में खड़े करते है। आज जिस सोशल मीडिया को एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट उसी पर है। क्योंकि यह सोशल मीडिया सूचना संवाहक तो बन गया है लेकिन अभी तक विचार का नही बन पाया है। फिर सोशल मीडिया पर आयी जानकारी के स्त्रोत का पता लगाने के लिये तो कैलिफार्निया का सहयोग चाहिए यह इन चुनावों के दौरान प्रदेश भाजपा द्वारा साईबर एक्ट के तहत दायर एक शिकायत के जवाब में हमारे सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर आयी पोस्ट से भाजपा का जो नुकसान होना था वह तो हो गया और उस पर दर्ज शिकायत पर कारवाई होने तक तो शायद दूसरा चुनाव भी आ जाये। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस सोशल मीडिया की अपनी प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं वह मीडिया के लिये चुनौती या संकट नही हो सकता। सोशल मीडिया एक त्वरित प्रचार का माध्यम मात्र है और उसे प्रचार मंच से अधिक मान देने की आवश्यकता नही है। आज जब कोई विचार या सचूना पाठकों के सामने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ रखी जाती है तब उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नही उठ पाते हैं। आज पत्रकार यदि अपनी सूचना पर आश्वस्त हैं तो उस पर कोई संकट नही है। क्योंकि आज पाठक भी पत्रकार पर हर समय उसी तरह नज़र रखे हूए है जिस तरह पत्रकार रखता है। आज यदि पत्रकार की करनी और कथनी में कोई अनतर नही होगा तो समाज हर समय उसके साथ खड़ा नज़र आयेगा। इसलिये जब पत्रकार स्वयं पर विश्वास कर पायेगा तब उसकी विश्वसनीयता को कोई संकट नही है।

खुशियों का पैमाना बनती जा रही शराब

वैसे तो हमारे देश में अनेक समस्याएँ हैं जैसे गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार आदि लेकिन एक समस्या जो हमारे समाज को दीमक की तरह खाए जा रही है, वो है शराब।

दरअसल आज इसने हमारे समाज में जाति, उम्र, लिंग, स्टेटस, अमीर, गरीब, हर प्रकार के बन्धनों को तोड़ कर अपना एक खास मुकाम बना लिया है।

समाज का हर वर्ग आज इसकी आगोश में है।

अब यह केवल गम भुलाने का जरिया नहीं है, बल्कि खुशियों को जाहिर करने का पैमाना भी बन गया है।

आनंद के क्षण, दोस्तों का साथ, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन, कोई भी पार्टी, जन्मदिन हो या त्यौहार ये सब पहले बड़ों के आशीष और ईश्वर को धन्यवाद देकर मनाए जाते थे लेकिन आज शराब के बिना सब अधूरे हैं।

हमारे समाज की बदलती मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शराब ही इस पृथ्वी की एकमात्र चीज है जिसके लिए इसे न पीने वाले से दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं और उस बेचारे को इसे न पीने के अनेकों तर्क देने पड़ते हैं।

कारण, विज्ञापनों के मायाजाल और उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे जीवन की परिभाषाएँ ही बदल दी हैं।

कुछ मीठा हो जाए, ठण्डा मतलब कोका कोला, खूब जमेगा रंग जब मिलेंगे तीन यार, जैसी बातें जब वो लोग कहते हैं जिन्हें आज का युवा अपना आइकॉन मानता हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पर कितना गहरा पड़ता है यह इन उत्पादों की वार्षिक सेल रिपोर्ट बता देती है।

और इस सबका हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आज के भौतिवादी युग में जीवन जीने के इस आधुनिक मंत्र से लगाया जा सकता है कि, 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' इसलिए 'जी भर के जी ले मेरे यारा'।

क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस नए मंत्र से इन कम्पनियों का बढ़ता मुनाफा हमारे समाज के घटते स्वास्थ्य और चरित्र के गिरते स्तर का द्योतक बनता जा रहा है?

विभिन्न अध्ययनों से यह बात साबित हो चुकी है कि हमारे आस पास बढ़ते बलात्कार और अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण शराब है।

कितनी ही महिलाओं और बच्चों को शराब का नशा वो जख्म दे गया जिनके निशान उनके शरीर पर से समय ने भले ही मिटा दिए हों लेकिन रूह तो आज भी घायल है। (यह सिद्ध हो चुका है कि घरेलू हिंसा में शराब एक अहम कारण है)।

कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पिता के साथ प्यार दुलार का उनका हक शराब ने ऐसा छीना कि वे अपने बचपन की यादों को भुला देना चाहते हैं।

तो फिर इतना सब होते हुए भी ऐसा क्यों है कि हम इससे मुक्त होने के बजाय इसमें डूबते ही जा रहे हैं?

ऐसा नहीं है कि सरकारें इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती परेशानी यह है कि अपेक्षित नतीजे नहीं निकलते।

विश्व की अगर बात की जाए तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1920 में अपने संविधान में 18 वाँ संशोधन करके मद्य पेय के निर्माण एवं बिक्री पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा कर इसके सेवन पर रोक लगाने के प्रयास किए थे जिसके परिणामस्वरूप लोग अवैध स्रोतों से शराब खरीदने लगे और वहाँ पर शराब के अवैध निर्माताओं एवं विक्रेताओं की समस्या उत्पन्न हो गई। अन्ततः 1933 में संविधान संशोधन को ही निरस्त कर दिया गया।

यूरोप के अन्य देशों में भी 20 वीं सदी के मध्य शराब निषेध का दौर आया था जिसे लोकप्रिय समर्थन नहीं मिलने की स्थिति में रद्द करना पड़ा। कुछ मुस्लिम देश जैसे सउदी अरब और पाकिस्तान में आज भी इसे बनाने या बेचने पर प्रतिबंध है क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है।

भारत की अगर बात करें तो भले ही गुजरात और बिहार में शराबबंदी लागू हो (यह व्यवहारिक रूप से कितनी सफल है इसकी चर्चा बाद में) लेकिन आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में यह नाकाम हो चुकी है।

केरल सरकार ने भी 2014 में राज्य में शराब पर प्रतिबंध की घोषणा की थी जिसके खिलाफ बार एवं होटल मालिक सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को बहाल रखकर इस प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त राज्य में पर्यटन को देखते हुए केवल पाँच सितारा होटलों में इसकी अनुमति प्रदान की।

तो सरकार भले ही शराब बिक्री से मिलने वाले बड़े राजस्व का लालच छोड़ कर इस पर प्रतिबंध लगा दे लेकिन उसे इस मुद्दे पर जनसमर्थन नहीं मिल पाता। बल्कि हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ महिलाओं के दबाव में सरकार इस प्रकार का कदम उठाती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को मात्र दो साल में अपने निर्णय को वापस लेना पड़ता है। कारण कि जो महिलाएं पहले इस बात से परेशान थीं कि शराब उनका घर बरबाद कर रही है अब इस मुश्किल में थीं कि घर के पुरुष अब शराब की तलाश में सीमा पार जाने लगे थे। जो पहले रोज कम से कम रात में घर तो आते थे अब दो तीन दिन तक गायब रहने लगे थे। इसके अलावा दूसरे राज्य से चोरी छिपे शराब लाकर तस्करी के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ जाते थे तो इन्हें छुड़ाने के लिए औरतों को थाने के चक्कर काटने पड़ते थे सो अलग।

जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहाँ की व्यहवहारिक सच्चाई सभी जानते हैं। इन राज्यों में शराब से मिलने वाला राजस्व सरकारी खजाने में न जाकर प्रइवेट तिजोरियों में जाने लगा है और जहरीली शराब से होने वाली मौतों की समस्या अलग से उत्पन्न हो जाती है।

इसलिए मुद्दे की बात तो यह है कि इतिहास गवाह है, कोई भी देश कानून के द्वारा इस समस्या से नहीं लड़ सकता।

चूंकि यह नैतिकता से जुड़ी सामाजिक समस्या है तो इसका हल समाज की नैतिक जागरूकता से ही निकलेगा। और समाज में नैतिकता का उदय एकाएक संभव नहीं है, किन्तु इसका विकास अवश्य किया जा सकता है। नैतिकता से परिपूर्ण समाज ही इसका स्थायी समाधान है कानूनी बाध्यता नहीं।

डा. नीलम महेंद्र

इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के

सृष्टि की सुंदर वाटिका में खिले तरह–तरह के फूलों की गंध, रूप, रस और रंग का आकर्षण और सौंदर्य भी जुदा–जुदा होता है। इलाहाबाद के 'आनंद भवन' में पं. मोतीलाल नेहरू के घर जन्मे जवाहरलाल सचमुच दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार थे।

अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सपना देखना भी तब जुर्म में शुमार था। भारत की जनता दासता का बोझ ढोते–ढोते थक गई थी। देश का स्वाभिमान धीरे–धीरे जाग रहा था। आपस में विभाजित सामंत और राजे–महाराजे अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करने को तैयार थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने अफ्रीका से लौटे गाँधी के हाथों में स्वदेशी आंदोलन की बागडोर सौंपकर जब देश के युवाओं को आजादी की जंग में कूदने का आव्हान किया, तब जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी।

अंग्रेजों ने गाँधी और जवाहर का राजनीतिक लोहा माना और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को भारत से अपना बोरिया–बिस्तर बाँधना पड़ा। देश स्वतंत्र होने के बाद नेहरूजी ने देश के नवनिर्माण की जो वैज्ञानिक आधारशिला रखी, उसी का परिणाम है कि आज हम विश्व में अपने ज्ञान–विज्ञान और टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया से मनवा सके हैं। अंतरिक्ष विज्ञान हो या परमाणु विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा विश्व में आज एक सम्मानजनक स्थान है और आर्थिक दृष्टि से भी हमारा आधार पहले से मजबूत है। दूरदर्शी जवाहरलाल की दृष्टि एवं स्वप्नदर्शिता का ही यह कमाल था कि आज से ६० वर्ष पूर्व ही उन्होंने देश को नई वैज्ञानिक संस्कृति के रंग में रंगना शुरू कर दिया था।

वे भारत के बच्चों, तरुणों, युवाओं एवं युवतियों में एक नया उत्साह भर देना चाहते थे। वे इस देश को धरती पर एक खुशहाल राष्ट्र देखना चाहते थे। बच्चों के प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह उनके कोमल मन का प्रमाण था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विश्वभर के बच्चों के चाचा नेहरू का जन्म दिन बाल दिवस प्रतिवर्ष १४ नवंबर को कुछ नए सवाल लेकर आता है। आज भारत सहित समूचे विश्व में विशेषकर एशिया, अफ्रीका और विकासशील दुनिया में बच्चों के मानवीय अधिकारों का जो अपहरण और उत्पीड़न हो रहा है, उसे देखकर आज चाचा नेहरू की आत्मा अवश्य रो रही होगी।

चाचा नेहरू बच्चों में कल की दुनिया की बेहतर तस्वीर देखते थे। उन्हें बेतहाशा प्यार देना चाहते थे और चाहते थे कि वे आगे चलकर इस धरती पर बसी दुनिया को खूबसूरत बनाएँ, सजाएँ, सँवारें और यह धरती शांति और सहअस्तित्वपूर्ण मानवीय रिश्तों का एक सुखी–समृद्ध परिवार बन सके। चाचा नेहरू जब आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की जेल की सलाखों के पीछे थे, तब उन्होंने अपनी नन्ही–सी बेटी इंदु (इंदिरा गाँधी) को निरंतर कुछ ऐसे पत्र लिखे थे, जिनमें धरती पर दुनिया के बनने और मानव सभ्यता के विकास की सिलसिलेवार कहानी कही गई थी। यह पुस्तक 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' शीर्षक से प्रकाशित है और दुनिया के करोड़ों बच्चे इसे पढ़ चुके हैं।

दरअसल चाचा नेहरू यदि भारत के प्रधानमंत्री न होते तो भी वे एक महान लेखक अवश्य होते। उनकी 'भारत एक खोज' कृति अपने देश की पूरी जीवनगाथा है। एक पूरा जीवंत इतिहास इस कृति के भीतर अँगड़ाई ले रहा है। भारत के महान लेखक और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' की भूमिका में चाचा नेहरू ने हमारी राष्ट्रीय एकता के सूत्रों की खोज पर दिनकर जी को बधाई देते हुए भारत जैसे विविधवर्णी देश के लिए इस तरह की कृतियों के लेखन की आवश्यकता को निरूपित किया है।

आज देश के बच्चे बेहाल हैं। उनकी सेहत सबके लिए बेहद चिंता का विषय है। बाल श्रमिक निरंतर बढ़ रहे हैं । समाज की आर्थिक विषमता उसकी जड़ में है। बालक–बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पूरी होते–होते तमाम बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। पालकों के पास देने के लिए फीस नहीं है। शिक्षा महँगी हो गई है। शिक्षा का व्यापारीकरण देश के बच्चों के जीवन और भविष्य के लिए श्राप बन गया है। बच्चे पीड़ित हैं। उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं। उनका यौन शोषण आम बात है। उनकी हत्याएँ अखबार की सुर्खियों में अक्सर रहती हैं। बच्चों की मानसिक, शारीरिक विकलांगता एवं रोगों के प्रति जागरुकता अभियान में आज खोखलापन है। अनपढ़ और अशिक्षित बच्चे भीख माँगने को विवश हैं। अनाथालयों में शिशुओं को उचित संरक्षण का सर्वथा अभाव है। 'बाल दिवस' मनाने की सार्थकता पर उठे ये यक्ष प्रश्न हर बार हमें झकझोर जाते हैं।

क्या चाचा नेहरू का यही स्वप्न था। बच्चों के प्यारे चाचा आज के भारत में हो रही बच्चों की ये दुर्दशा यदि देख पाते तो शायद उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। क्या बच्चों के जीवन–भविष्य से खिलवाड़ करती इस निर्दयी दुनिया से लड़ने की चुनौती आज हमारे सामने नहीं है? क्यों न हम बच्चों के साथ मिलकर उन्हें उनकी इस जंग में जिताने के लिए कुछ काम करें। यदि हम भारत एवं विश्व के बच्चों को उनकी खुशियाँ लौटा सकें तो यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

चाचा नेहरू के प्रेरक और दिलचस्प प्रसंग

चाचा नेहरू अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इसकी वजह थी उनका हास्यप्रिय स्वभाव और नन्हे बच्चों के प्रति अनुराग। चाचा नेहरू के कुछ दिलचस्प किस्से.....

नेहरू जी और सोना

किस्सा 1962 का है। तब चीन ने भारत पर एकाएक हमला कर दिया था, जिसमें हमारे देश को काफी हानि उठानी पड़ी थी। उस युद्ध के बाद ही 14 नवंबर को पं. जवाहरलाल नेहरू का 73वां बर्थडे आया। पंजाब की जनता ने प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में योगदान देने के लिए नेहरूजी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर उन्हें सोने से तौलने का निर्णय किया। यह तय किया गया कि नेहरूजी के वजन से दो गुना सोना चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में मदद के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में दिया जाए।

नेहरूजी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनका वजन किया गया। एकत्रित सोने में से उनके वजन के दो गुने के बराबर सोना तौला गया। दो गुना सोना लेने पर भी एकत्रित सोने का काफी भाग बचा रह गया। बचे हुए सोने को देखकर नेहरूजी ने बड़ी भोली मुखमुद्रा बनाते हुए कहा, क्या ये बचा हुआ सोना वापस ले जाओगे? नेहरूजी के मासूमियत भरे शब्दों से हंसी का वातावरण छा गया और बचा हुआ सोना भी प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में दे दिया गया।

जब चाचा नेहरू बच्चे थे

जवाहरलाल नेहरू के बाल्यकाल की घटना है। उनके घर पिंजरे में एक तोता पलता था। पिता मोतीलालजी ने तोते की देखभाल का जिम्मा अपने माली को सौंप रखा था। एक बार नेहरूजी स्कूल से वापस आए तो तोता उन्हें देखकर जोर–जोर से बोलने लगा। नेहरूजी को लगा कि तोता पिंजरे से आजाद होना चाहता है। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता आजाद होकर एक पेड़ पर जा बैठा और नेहरूजी की ओर देख–देखकर कृतज्ञ भाव से कुछ कहने लगा। उसी समय माली आ गया। उसने डाँटा–'यह तुमने क्या किया! मालिक नाराज होंगे।

बालक नेहरू ने कहा–'सारा देश आजाद होना चाहता है। तोता भी चाहता है। आजादी सभी को मिलनी चाहिए।

जब चाचा नेहरू ने चुप कराया रोते बच्चे को

चाचा नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री का सरकारी निवास था। एक दिन तीन मूर्ति भवन के बगीचे में लगे पेड़–पौधों के बीच से गुजरते हुए घुमावदार रास्ते पर नेहरूजी टहल रहे थे। उनका ध्यान पौधों पर था। वे पौधों पर छाई बहार देखकर खुशी से निहाल हो ही रहे थे तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नेहरूजी ने आसपास देखा तो उन्हें पेड के बीच एक–दो माह का बच्चा दिखाई दिया जो दहाड़ मारकर रो रहा था। नेहरूजी ने मन ही मन सोचा– इसकी मां कहां होगी? उन्होंने इधर–उधर देखा। वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी।

चाचा ने सोचा शायद वह बगीचे में ही कहीं माली के साथ काम कर रही होगी। नेहरूजी यह सोच ही रहे थे कि बच्चे ने रोना तेज कर दिया। इस पर उन्होंने उस बच्चे की मां की भूमिका निभाने का मन बना लिया। नेहरूजी ने बच्चे को उठाकर अपनी बांहों में लेकर उसे थपकियां दीं, झुलाया तो बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बच्चे को मुस्कुराते देख चाचा खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की मां दौड़ते वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका बच्चा नेहरूजी की गोद में मंद–मंद मुस्कुरा रहा था।

चाचा नेहरू और गुब्बारे वाला बच्चा

ऐसे ही एक बार जब पंडित नेहरू तमिलनाडु के दौरे पर गए तब जिस सड़क से वे गुजर रहे थे वहां वे लोग साइकलों पर खड़े होकर तो कहीं दीवारों पर चढ़ कर नेताजी को निहार रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहां समझ आया वहां खड़े होकर नेहरू को निहारने लगा। इस भीड़भरे इलाके में नेहरूजी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के तरह–तरह के रंग–बिरंगी गुब्बारे मानो पंडितजी को देखने के लिए डोल रहे हो। जैसे वे कह रहे हों हम तुम्हारा तमिलनाडु में स्वागत करते है।

नेहरूजी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुंची तो गाड़ी से उतरकर वे गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े तो गुब्बारे वाला हक्का–बक्का रह गया। नेहरूजी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाए और वहां उपस्थित सारे बच्चों को वे गुब्बारे बंटवा दिए। ऐसे प्यारे चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। नेहरूजी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे–जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुंचे बच्चों ने चाचा नेहरू–चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहां का वातावरण उल्लासित कर दिया। तभी से वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

साभार www.hindi.webdunia.com से

गुडिया मामले में जैदी व बाकियों के वायस सैंपल लेने को अदालत में अर्जी दाखिल

शिमला/शैल। गुडिया गैंगरेप और मर्डर मामले में गिरफ्तार आरोपी सूरज सिंह की पुलिस लॉकअप में कत्ल के मामले में एसआईटी के मुखिया जहूर हेदर जैदी और बाकी आरोपियों के वायस सैंपल लेने में पेंच फंस गया हैं। सीबीआईने इन सभी के वायस सैंपल लेने के लिए सीजेएम रंजित सिंह ठाकुर की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई हुई। लेकिन आरोपियों की ओर से अदालत में वकील ही पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर को टाल दी। अदालत में इस अर्जी पर विचार होना था।

सीबीआई ने सुबह11 बजे के करीब आईजी जैदी समेत आठों पुलिस वालों को सीजेएम रंजित सिंह की अदालत में पेश किया। इससे पहले इन आरोपियों की पेशी वीडियो कांफेंसिंग के जरिए होती थी। आरोपियों ने अदालत में अर्जी दी कि उनके वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन से उनके मामले की पैरवी करने की इजाजत मांगी हैं। उन्हें इजाजत नहीं मिली हैं, इसलिए मामले की सुनवाई टाल दी जाए।

सीजेएम रंजित सिंह ठाकुर ने उनकी अर्जी पर मामले की सुनवाई 20 नंवबर तक टाल दी हैं।

गौरतलब हो कि गुडिया गैंगरेप व मर्डर केस में जिला बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया था कि इस मामले की पैरवी जिला बार एसोसिएशन का कोई भी वकील नहीं करेगा। वीरभद्र सरकार की ओर आईजी जैदी की कमान में गठित एसआईटी के आठ सदस्यों को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो वरिष्ठ वकील अजय कोछड़ समेत तीन चार वकील आरोपी पुलिस वालों की ओर से अदालत में पैरवी करने को हाजिर हो गए। इस पर इन वकीलों की बार एसोसिएशन की सदस्यता रदद कर दी।

ये वकील इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी बनाकर जिला बार भेजी। लेकिन शुरू में कोई सहमति नहीं बनी। आखिर में ये तय हुआ कि वो जिला एसोसिएशन को मामले की पैरवी करने की मंजूरी लेने के लिए अर्जी भेजेंगे। इन वकीलों ने दो तीन दिन पहले ये अर्जी जिला बार एसोसिएशन को भेजी है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी ने कहा कि कार्यालय में इस तरह की अर्जी आई हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंची व एसोसिएशन 20 नवंबर से पहले उनकी अर्जी पर फैसला ले लेंगी।

बार एसोसिएशन में आरोपियों की अर्जी लंबित होने की वजह से वो पैरवी करने अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे में अदालत ने सुनवाई आगे को टाल दी।

लाला लाजपतराय की पुण्य तिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित

शिमला/शैल। पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की पुण्य तिथि पर स्कैन्डल प्वाइंट स्थित उनकी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित कर श्रदांजलि दी गई। इस अवसर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री विद्या स्टोक्स ने उन्हें महान स्वतन्त्रता सेनानी बताते हुए देश के लिए दी गई उनकी शहादत को याद किया।

उन्होंने कहा कि वीर स्वतन्त्रता सेनानियों तथा जान की बाजी लगा कर हमारे देश की सीमाओं व आन्तरिक सुरक्षा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी महान सपूत शहीदों को भी आज के इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं।

महापुरूषों के त्याग के परिणामस्वरूप राष्ट्र आज अपनी एकता, अखण्डता व सम्प्रभूता को कायम रखने में सक्षम हुआ है। उन्होंने युवा पीढी से आहवान किया कि हमें अपने स्वतन्त्रता सेनानियों तथा देश पर कुर्बान होने वाले वीर पुरूषों के सम्बन्ध में जानकारी रखना अत्यन्त आवश्यक है यही उनके प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी।

इस अवसर पर महा महिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से उनके सचिव राकेश शर्मा ने लाला लाजपतराय जी को भावभीनी श्रृद्धांजलि अर्पित की। महापौर नगर निगम शिमला कुसुम सदरेट, उप–महापौर, पूर्व महापौर सोहन लाल, आयुक्त नगर निगम जी. सी. नेगी, पार्षदों एवं पूर्व पार्षदगणों के अतिरिक्त नगरवासियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

डेंगू को लेकर कौल सिंह ने तलब किए अफसर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों, विशेषकर सोलन जिला में डेंगू महामारी को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य सम्बधित विभागों के अधिकारियों को तलब किया ।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर डेंगू एक भयावह महामारी है और विभाग ने इससे निपटने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए हैं। राज्य के विभिन्न भागों में डेंगू की आशंका को लेकर 2,621 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई हैं जिनमें से 401 मामले पॉजीटीव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले सोलन जिला में डेंगू के 265 मामले पॉजीटिव पाए गए हैं और इनमें से अधिकांश मामले परवाणू, बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ में कार्यरत प्रवासी मजदूरों में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की सतर्कता के कारण डेंगू से अभी तक कोई भी मृत्यु नहीं हुई है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में डेंगू की नि:शुल्क जॉच की जा रही है और पॉजीटिव मामलों में रोगियों को नि:शुल्क दवाईयां व उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग स्थानीय निकायों को संबंधित क्षेत्रों में स्प्रे करने के लिये नि:शुल्क फॉगिंग मशीनें उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने स्थानीय निकायों से आह्वान किया कि किसी भी स्थान पर पानी एकत्र न होने दें क्योंकि चार–पांच दिनों तक एक जगह पर ठहरा साफ जल भी डेंगू के मच्छर के पैदा होने का कारण बन सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन सोलन को एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों के विभिन्न दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीएम नालागढ़ को भी क्षेत्र का विस्तृत दौरा व निरीक्षण करने तथा स्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के सचिव को ओद्यौगिक इकाईयों से निकल रहे प्रदूषित तरल का समुचित निदान सुनिश्चित करवाने तथा पानी के एक जगह पर एकत्र होने को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के सघन निरीक्षण के आदेश दिए हैं।

डेंगू महामारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाईजरी भी जारी की गई है।

इन्दिरा गांधी को उनके जन्म दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनकी 100वीं जयन्ती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रीमती गान्धी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल की ओर से श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

हिमुडा के अधयक्ष यशवन्त छाजटा, हि.प्र. महिला आयोग की अध्यक्षा जैनव चन्देल, नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, पूर्व महापौर जैनी प्रेम तथा सोहन लाल, नगर निगम के पार्षदगण, नगर निगम आयुक्त जी.सी. नेगी, शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा स्कूली बच्चों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने भजन एवं देश भक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए।

सरकार करेगी प्रतिभूतियों की नीलामी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 साल की अवधि के साथ 300 करोड़ रुपये की राशि के लिये नीलामी के माध्यम से दिनांकित प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) को बेचने की पेशकश की है। ये प्रतिभूतियां कम से कम 10000 रुपये की न्यूनतम राशि तथा उसके बाद 10000 रुपये के गुणक के आधार पर जारी की जाएंगी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने मुम्बई कार्यालय में 21 नवम्बर, 2017 को की जाएगी और यह कई मूल्य प्रारूप के अंतर्गत मुनाफा आधारित होगी।

उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान प्रणालियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में नीलामी के लिये बोलियां जमा कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी वित्त विभाग की 17 नवम्बर, 2017 को जारी अधिसूचना संख्या फिन–2–सी (12)–3/2017 से प्राप्त की जा सकती है।

कानूनी अधिकारों व मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता रैली का आयोजन

शिमला/शैल। लोगों को उनके विभिन्न कानूनी अधिकारों व मुफ्त कानूनी सहायता के सम्बन्ध में जागरूक करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण संजय करोल ने इस रैली को उच्च न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस रैली में माननीय न्यायधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा तथा न्यायमूर्ति सी.वी. बरोवालिया, एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा, अन्य न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ शिमला नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह रैली उच्च न्यायालय परिसर से मॉल रोड होते हुए एजी ऑफिस चौक पर सम्पन्न हुई।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने RTI पर चलाया विशेष अभियान

शिमला/शैल। प्रदेश के समस्त जिलों में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को 'सूचना का अधिकार' बारे विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में वन्दना कला मंच के कलाकारों द्वारा नारकंडा, थानाधार, ननखड़ी तथा देलठ में गीत–संगीत व नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को सूचना का अधिकार बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। प्रत्येक नागरिक को इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों व अधिकारों का प्रयोग करने बारे बताया। उन्होंने गीत एवं नाटक के माध्यम से इस अधिनियम का सही ढंग से प्रयोग करने बारे भी अपील की। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने सम्बंधी जागरूकता भी प्रदान की गई।

इंदिरा गांधी को याद करते हुए

श्रीमती इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी – लोकप्रिय नेता थी तथा कड़क नेता के रूप में मान्य रही। 1971 में बंगलादेश बना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था यद्यपि अब और एक न्यूज चैनल में तो बीजेपी प्रवक्ता संविद पात्रा ने साफ कहा कि अटल बिहारी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था... अब वे जानें, आज उनकी सरकार है अतः वे जो कहें वही 'सत्य' कहावत है – 'जहां राणा कहें वहें वहीं उदयपुर'। एक और बात नोट करने की है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ही देश में आर्थिक नीतियां पूंजीवादी नीतियों पर आधारित होने लगी थीं। डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया और भाजपा उसी रास्ते पर तेज दौड़ रही है।

– प्रभाकर चौबे –

श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू की अपेक्षा ज्यादा कठिनाइयों का संघर्ष का सामना करना पड़ा था और प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होने के लिए और भी ज्यादा कांटों भरी राह से गुजरना पड़ा था – जबरदस्त संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री बनने से लेकर अपने अंतिम सांस तक श्रीमती इंदिरा गांधी ने खूब संघर्ष किया, उन्हें केवल संघर्ष ही करते रहना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि (खासकर आजादी के बाद) वह एक डेमोक्रेटिक पार्टी होते हुए भी व्यक्ति (एक नेता) आश्रित पार्टी बन कर रही। आजादी के बाद प्रायः हर चुनाव में कांग्रेस ने गांधी – नेहरू के नाम पर वोट मांगना और जनता ने कांग्रेस को गांधी – नेहरू के नाम पर वोट दिया भी – 1964 में पं. नेहरू के निधन के बाद 1967 में हुए आम चुनाव में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा – उन्होंने गांधी – नेहरू के नाम पर वोट नहीं मांगा। चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया – लगातार चुनाव सभाएं लेती रहीं। इसी दौरान भुवनेश्वर की एक सभा में जब वे सम्बोधित कर रही थीं तो उपद्रव शुरू हो गया और किसी उपद्रवी ने उन पर पत्थर फेंका जो उनकी नाक पर लगा – जिसकी बाद में सर्जरी की गई। इस भयानक चोट के बावजूद वे आगे चुनाव प्रचार में लगी रहीं। राजनीतिक गणित के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था उस समय कि उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी जीत सकती है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में राजगोपालाचारी द्वारा की गई थी –

राजगोपालाचारी आजादी के बाद देश के प्रथम गवर्नर जनरल बनाये गए थे – कांग्रेस में वे इस पार्टी के प्रमुख स्तम्भ माने जाते थे। स्वतंत्र पार्टी को बड़े जमींदारों, राजवाड़ों व कुछ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का भरपूर समर्थन था। स्वतंत्र पार्टी का प्रभाव उड़ीसा व गुजरात में अधिक रहा। वैसे स्वतंत्र पार्टी का पराभव दृश्य से गायब होना देश में विशुद्ध पूंजीवाद के हित में विपरीत रहा। स्वतंत्र पार्टी वास्तव में पूर्णरूपेण पूंजीवादी पार्टी थी। इसे लेकर वर्तमान स्थिति को सामने रखकर बहस होनी चाहिए। आज कोई भी पार्टी 'विशुद्ध' पूंजीवादी पार्टी नहीं है। बहरहाल इस पर फिर कभी...। अभी तो इंदिरा जी पर ही बात को केन्द्रित रखा जाए वर्ना भटकाव निश्चित है।

ऊपर बताया गया है कि 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आम चुनाव लड़ा गया – इंदिरा गांधी ने धुआंधार प्रचार किया – उस समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबों (विशेषकर महिलाओं) के बीच 'अम्मा' नहीं बनी थीं। खैर आगे यह कि फरवरी 1967 में आम चुनाव हुए – परिणाम आए। परिणामों में कांग्रेस की सदस्य संख्या कम हो गई थी – कांग्रेस की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा था। चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस की भयानक गुटबंदी व इंदिरा गांधी विरोध की लाबी के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनौतियां तथा नीति संबंधी संघर्ष उभर कर सामने आने लगे खासकर आर्थिक नीतियों को लेकर पार्टी में दो खेमा उभर चुका था। उधर श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक साक्षात्कार में अपनी पक्षधरता या कहें पोलिटिक विचारधारा स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने साक्षात्कार में कहा था – ''आई एम सेंटरिस्ट, लीनिंग टू वर्ड ''लेफ्ट'' उनके इस स्पष्टीकरण ने कांग्रेस के दक्षिणपंथी खेमे में हलचल मचा दी थी – इससे खेमे में खलबली मच गई थी – खदबदा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने और यह कहने में हर्ज नहीं कि इसी के बाद से ही संगठन में दूसरा खेमा खुद को मजबूत कर श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्टी में कमजोर करने या जरूरत पड़े तो बाहर निकालने की तैयारी में जुट गया था। हद तो तब हो गई जब अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्थिक नीति का मसौदा पेश किया जबकि यह काम वित्त मंत्री को करना था और

ऐसा होने के बाद मीडिया में उन दिनों जमकर बहस छिड़ी और अंदाज लगाया जाने लगा कि अब श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे खेमे के खिलाफ सीधे संघर्ष में उतरेंगी। हुआ भी यही...।

श्रीमती इंदिरा गांधी को खुद को बनाए रखने तथा मजबूत होते रहने के लिए पार्टी के अंदर खूब संघर्ष करना पड़ा – यह दृश्टव्य है कि उन दिनों श्रीमती इंदिरा गांधी के आंतरिक संघर्ष में जनता की सहानुभूति श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ रही। इसका भी खास कारण है वह यह कि जनता पुराने परंपरावादी नेताओं से उकता गई थी और उनसे छुटी चाहती थी। शायद इसीलिए जब सिंडीकेट के खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना संघर्ष तेज किया। कांग्रेस कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों की छुटी कर दी तब देश की जनता उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की अपील से जनता प्रभावित रही – और शायद जनता के रुख को देखकर ही सांसदों – विधायकों ने इंदिराजी के केंडीडेट को व्होट दिया। यह श्रीमती इंदिराजी की राजनीतिक हौसले की जीत रही।

देश उस दौर में भयानक अन्न संकट, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, चारों ओर असंतोष ही असंतोष था – 65 से 67 दो साल लगातार अकाल पड़ा और 'लाल गेहूं' खाने की नौबत आई थी। उधर अंतरराष्ट्रीय स्थितियां भी भारत के प्रतिकूल बनाई जा रही थी। अमेरिकी प्रशासन लगातार इंदिरा गांधी पर उसकी नीति पर चलने व उसकी विस्तारवादी नीति तथा दुनिया भर में फैले 'सैन्य संगठनों' में शामिल होने दबाव डाल रहा था। इसी दबाव के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस के साथ 20 वर्षीय मैत्री सहयोग की संधि की और देश की दक्षिणपंथी ताकतों को यह संधि पसंद नहीं आ रही थी। यहां तक कि जय प्रकाश नारायण तक को यह नापसंद थी, लेकिन 1971 के पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इस संधि का परोक्ष लाभ देश को मिला। बंगलादेश के निर्माण में यह सिद्ध हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति व रणनीति एकदम सही थी। एक और बात का उल्लेख करना जरूरी है, इससे 1974 में शुरू हुआ जे.पी. आंदोलन को समझने में शायद मदद मिले।

1974 में शुरू हुए जबरदस्त आंदोलन के बाद एक समय सरकार से वार्ता का प्रस्ताव आया और जयप्रकाश नारायण ने संधि के वास्ते या कहें समझौता होने के लिए जो 30 सूत्री प्रस्ताव पेश किया उसमें 29वां पाईट यह था कि 1971 में हुए भारत – रूस की 20 साला संधि को रद्द किया जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह स्वीकार नहीं किया और वार्ता असफल हो गई जिसका परिणाम 1975 लगा आपातकाल रहा। दरअसल बहुत ही मजबूरी में आपातकाल लगाया गया था – भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन इंदिरा गांधी के त्यागपत्र मांगने में तब्दील हो गया तथा समय के साथ वह सम्पूर्ण क्रांति के नाम से प्रचारित किया जाने लगा। इस आंदोलन में समाजवादी, तथा फोरम ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज से प्रभावित 'साहित्य की स्वायत्तता' के प्रवक्ता साहित्यकार शामिल थे, लेकिन असल ताकत व इसे जनता तक ले जाने में जनसंघ व आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दरअसल असली ताकत तो इन्हीं की थी।

श्रीमती इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी – लोकप्रिय नेता थीं तथा कड़क नेता के रूप में मान्य रही। 1971 में बंगलादेश बना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था यद्यपि अब और एक न्यूज चैनल में तो बीजेपी प्रवक्ता संविद पात्रा ने साफ कहा कि अटल बिहारी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था... अब वे जानें, आज उनकी सरकार है अतः वे जो कहें वही 'सत्य' कहावत है – 'जहां राणा कहें वहें वहीं उदयपुर'। एक और बात नोट करने की है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ही देश में आर्थिक नीतियां पूंजीवादी नीतियों पर आधारित होने लगी थीं। डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया और भाजपा उसी रास्ते पर तेज दौड़ रही है। बहरहाल श्रीमती इंदिरा गांधी पर लिखते हुए उनके साहस की छवि उभर आती है। आपातकाल का विरोध वाम के एक धड़े ने किया था। लेकिन बाबा नागार्जुन ने ही सम्पूर्ण क्रांति की असलियत देखी,

मोहभंग हुआ तो लिखा –
खिचड़ी वैभव देखा हमने,
भोगा हमने क्रांति विलास।।

बहरहाल श्रीमती इंदिरा गांधी की छवि साम्राज्यवाद – विरोधी नेता के रूप में तथा साहसी कर्मठ नेता के रूप में सामने आती है।

साभार www.deshbandhu.co.in. से

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

नेगी की गिरफ्तारी के बाद सी.बी.आई. का अगला कदम क्या होगा उठने लगा सवाल

शिमला/शैल। बीते चार जुलाई को शिमला कोटखाई में हुए गुड़िया गैंगरेप एवम हत्या और फिर इसी प्रकरण में पकड़े गये कथित अभियुक्तों में से एक सूरज की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले में अब सीबीआई ने उस समय रहे शिमला के एसपी डी डब्ल्यू नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। नेगी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले को सुलझाने में बुरी तरह असफल रही है और पूरी जांच को भटका दिया गया है। दूसरी ओर इसी गिरफ्तारी पर प्रतिपक्ष नेता प्रेम कुमार धूमल ने अपनी प्रतिक्रिया में दावा किया है कि इस गिरफ्तारी से भाजपा की सारी आंशकाएं सही साबित हुई है। स्मरणीय है कि इस प्रकरण ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। लोगों का आक्रोश जनान्दोलन के रूप में सड़को पर आ गया था उग्र भीड़ ने कोटखाई पुलिसे स्टेशन को आग तक लगा दी थी। लोगों के इस उग्र आन्दोलन को देखते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 22 जुलाई से इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले है।

सीबीआई को मामला हाथ में लिये करीब चार महीने हो गये है। सीबीआई जांच पर प्रदेश उच्च न्यायालय लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जांच के नाम पर हुआ क्या कुछ तो यह तथ्य सामने आते हैं। चार जुलाई को यह पन्द्रह वर्षीय गुड़िया स्कूल से घर नहीं पहुंचती है। परिजन तलाश करते हैं उन्हे चार को कोई पता नही चलता है पांच को भी कोई पता नही चलता है और शाम को नौ बजे वह लड़की के मामा को इसकी सूचना देते हैं जो छ: को तलाश पर निकलता है उसे लड़की की लाश मिल जाती है और वह परिजनों और पुलिस को सूचित करता है। उसकी सूचना पर एफआईआर दर्ज होती है। आठ नौ को इस हत्या की खबरें छपती है इस पर उच्च न्यायालय दस को स्वत: संज्ञान लेकर पुलिस और सरकार से रिपोर्ट तलब करता है। खबरे छपने पर इसकी जांच के लिये नौ को पुलिस की एसआईटी गठित हो जाती है। 12 जुलाई को छ: लोगों से पूछताछ करती और 13 जुलाई को इन्हे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस पूछताछ और गिरफ्तारी से पहले ही चार लोगों के फोटो मुख्यमन्त्री की अधिकारिक फेसबुक पेज पर वायरल हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद हटा भी लिये जाते हैं परन्तु जो लोग गिरफ्तार किये जाते हैं उनमें इन लोगों में से कोई नही होता है जिनके फोटो वायरल हो चुके थे। इस पर पुलिस जांच पर पक्षपात के आरोप लग जाते हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है सरकार जन दबाव में मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लेती है इसी के साथ जब उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये मामला आया तब तक कोटखाई पुलिस थाने को आग लगा दिये जाने की वारदात घट चुकी थी और डीजीपी ने अपने शपथ पत्र में अदालत के सामने यह सारी स्थिति रख दी। इस पर अदालत ने भी सीबीआई को निर्देश दिये कि वह इस मामले की जांच तुरन्त अपने हाथ में ले। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिये थे कि 'The chief Secretary to the govt. of Himachal Pradesh shall ensure that appropriate action in taken against officials /officers/ functionaries of the state, in accordance with law. Within a period of two weeks from today, we shall independently examine the matter and take approriate action. मुख्य सचिव ने यह कारवाई कोटखाई थाना प्रकरण सहित पूरे मामले में करनी थी लेकिन इस कारवाई के संद्धर्भ में भी आज तक कोई जानकारी बाहर नही आई है। गुड़िया के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट चर्चा में आयी है उसके मुताबिक गुड़िया की हत्या चार जुलाई को ही पांच से छ: बजे के बीच हो गयी थी। इसके मुताबिक गैंगरेप से लेकर हत्या तक पूरे अपराध को दो घन्टे में ही अंजाम दे दिया। क्या यह संभव हो सकता है इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नही हो पाया है।

गुड़िया प्रकरण में कुछ बड़े सवाल

अब सीबी आई के सामने दो मामले हैं एक गुड़िया के गैंगरेप और हत्या का, दूसरा है इसी प्रकरण में पकड़े गये एक संदिग्ध की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। गुड़िया प्रकरण में जो संदिग्ध पकड़े थे उनके खिलाफ 90 दिन के भीतर पुलिस/सीबीआई अदालत में चालान दायर नही कर पायी और उनको ज़मानत मिल गयी है। यह ज़मानत तकनीकी आधार पर है गुण –दोष के आधार पर नहीं। इसलिये इसे क्लीन चिट नही कहा जा सकता। सीबीआई इन संदिग्धों का नार्को भी करवा चुकी है। लेकिन इस नार्को में क्या हुआ है इसका भी कोई खुलासा बाहर नही आया है। एक संदिग्ध की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के लिये सीबीआई पूरी एसआईटी को हिरासत में ले चुकी है। उच्च न्यायालय ने 30 नवम्बर तक इनके खिलाफ चालान दायर करने के निर्देश दे रखे हैं यदि तब तक चालान दायर नही होता है फिर इनको भी तकनीकी आधार पर ज़मानत मिल जायेगी। अब सीबीआई ने इसी कस्टोडियल डैथ के लिये डी डब्ल्यू नेगी को हिरासत में लिया है। नेगी पर आरोप है कि उन्होने इस प्रकरण में गलत मामला दर्ज किया। तथ्यों को छुपाया गया। नेगी पर इन आरोपों को आधार उनकी कुछ अधिकारियों और अन्य लोगों से हुई बातचीत का रिकार्ड सामने कहा जा रहा है। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक कस्टोडियल डैथ को लेकर हिरासत में चल रहे एसआईटी के सदस्यों से कोई बड़ी जानकारी नही मिल पायी हैं सीबीआई ने एसआईटी के सदस्यों के आवाज के सैंपल लेने के लिये अदालत में याचिका दायर कर रखी है। लेकिन इस पर कोई फैसला नही हो पाया क्योंकि अभियुक्तों की ओर से अदालत में कोई वकील पेश नही हुआ।

पुलिस कस्टडी में हुई मौत के लिये पुलिस ने मृतक सूरज और दूसरे अभियुक्त राजू के बीच झगड़ा होना कहा है। लेकिन सीबीआई ने पुलिस थ्योरी को न मानते हुए एसआईटी को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई असली हत्यारे को चिन्हित नही कर पायी है। अब सवाल उठता है कि क्या सूरज की मौत पुलिस की पूछताछ में कोई ज्यादती होने से हो गयी या फिर उसे नीयतन किसी को बचाने के लिये मारा गया? यदि किसी को बचाने के लिये मारा गया तो क्या इसके लिये पुलिस पर किसी बडे का दवाब था या फिर मोटे पैसे का खेल था? यदि दवाब था तो किसका और क्यों? यदि मोटे पैसे का खेल था तो यह पैसा कौन दे रहा था। एसआईटी के सदस्यों को इन्ही सवालों के लिये हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक सफलता के नाम पर सीबीआई खाली हाथ है। इन्ही सवालों के लिये अब डी डब्ल्यू नेगी को पकड़ा गया है। यहीं पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सीबीआई ने गुड़िया प्रकरण में जिन अभियुक्तों का नार्को करवाया था क्या उस नार्को में भी कोई ठोस लीड हाथ नही लगी है? क्योंकि इन्ही अभियुक्तों में से एक की गाड़ी गुड़िया को स्कूल से लाने से लेकर उसके शव को ले जाने तक में प्रयुक्त हुई कही गयी है, जिसका सीधा अर्थ है कि उसको तो यह अवश्य पता है कि किसके कहने पर उसने गाड़ी प्रयोग की? क्योंकि जो लोग पुलिस ने पकड़े थे उनसे ही गुड़िया के मुजरिम की जानकारी मिलने की सबसे बड़ी संभावना थी। उनके नार्को में तो यह जानकारी होना आवश्यक है लेकिन इन लोगों के नार्को के बाद भी यदि सीबीआई गुड़िया के किसी भी दोषी को नही पकड़ पायी है। तो इसका सीधा अर्थ है कि इन लोगों का इस गुडिया मामले से कोई वास्ता ही नही रहा है। तब फिर हटकर सन्देह की सूई कोटखाई पुलिस की ओर घूमती है कि उसने असली गुनाहगारों को बचाने का खेल पहले ही दिन रच दिया था और इस कड़ी में जिन लोगों के फोटो वायरल हुए और फिर पोस्ट से हटा लिये गये यह इस प्रकरण को सुलझाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, लेकिने इस संदर्भ में अभी तक सीबीआई के कोई कदम सामने नही आये है। अब डी डब्लू नेगी पर यदि यह आरोप है कि उन्होने जानबूझकर तथ्यों को छुपाकर गलत मामला दर्ज करवाया तो फिर सवाल उठता है कि नेगी ने किसके ईशारे पर यह सब किया जो पुलिस अधिकारी अब तक हिरासत में है। उनका भविष्य तो खत्म हो जायेगा यदि वह किसी को बचाने के प्रयास में अबतक खामोश बैठे है। क्योंकि कस्टोडियल डैथ नीयतन है या स्वभाविक परिस्थितियों का परिणाम है यह तो यही लोग जानते हैं। नेगी की हिरासत के बाद यदि सीबीआई कुछ और गिरफ्तारियों को 30 नवम्बर से पहले अंजाम नही देती है तो तय है कि पहले से हिरासत में चल रहे एसआईटी के सदस्यों को भी ज़मानत मिल जायेगी और यह ज़मानत मिलने का अर्थ होगा कि गुड़िया से लेकर सूरज की हत्या तक सीबीआई पूरी तरह खाली हाथ है तथा अन्धेरे में तीर चला रही है या फिर वह भी शिमला पुलिस की तरह बचाने के प्रयास में लग गयी है। क्योंकि यदि सीबीआई भी कस्टोडियल डैथ जैसे स्पाट मामले को नही सुलझा पाती है तो फिर उसकी काबीलियत से ज्यादा उसकी नीयत पर ही सवाल उठने शुरू हो जायेंगे।

एनजीटी के आदेशों से

.....पृष्ठ 1 का शेष

this committee should be carried out by the state government and all its departments as well as local authorities without default and delay. ट्रिब्यूनल ने यह आदेश योगेन्द्र मोहन सेन गुप्ता और शीला मल्होत्रा की याचिका पर सुनाये हैं। ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के टीसीपी और प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड के 20 सदस्यों के खिलाफ कारवाई करने की भी अनुशंसा की है।

एनजीटी के इन आदेशों से प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गयी है क्योंकि राजधानी शिमला में अवैध निर्माण के हजारों मामलें हैं बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यह अवैध निर्माण अपरोक्ष में राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए है। क्योंकि इन्हें नियमित करने के लिये सरकार नौ बार रिटैन्शन पॉलिसियां ला चुकी है। प्रदेश उच्च न्यायालय भी इन निर्माण पर कई बार तल्ख टिप्पणीयां कर चुकी है। एनजीटी के इन आदेशों के बाद नगर निगम शिमला के भी कई पार्षद इन्हे उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला लेने का विचार बना रहे हैं। इन आदेशों की अनुपालना करना सरकार के लिये भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

इन आदेशों के बाद नये निमार्णो के लिये बहुत सारी कठिनाईयां पैदा होने की आशंका हो गयी है। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में निमार्ण नही हो सकेगा जिनकी ढलान 35% से अधिक होगी। इन आदेशों के बाद स्मार्ट सिटी की सारी परियोजना का प्रारूप भी अब नये सिरे से बनाने की आवश्यकता आ खड़ी होगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारे ऐसे कार्य प्रायोजित है जिनकी अनुमति इन आदेशों के तहत मिल पाना संभव नही होगा।